



खुलने से पहले ही देश के सबसे बड़े आईपीओ में आई गिरावट

मुंबई। कार निर्माण कंपनी हुंडई मोटर इंडिया देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है, जिसका इयू साइज 27,870.16 करोड़ रुपए है। यह आईपीओ 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक निवेश के लिए खुला रहेगा। इस दौरान निवेशक इसके लिए बोली लाला सकते। कंपनी इस आईपीओ के तहत कोई फेस शेयर जारी नहीं करेगी। कुल 1,224 करोड़ रुपए शेयर जारी होंगे वे शेयर ऑफर फॉर सेल (ओफएस) के तहत जारी किए जाएंगे। इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में अच्छी रिसंसन्स नहीं मिल रहा है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में रिसॉन्स अच्छी रिसंसन्स नहीं मिल रहा है।

एलआईसी ने पॉलिसी के नियम बदले, योजना में एंट्री उम्मीद हटाई।

नई दिली। देश की प्रमुख बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एसआईसी) ने अपने न्यू एंडोमेंट्स प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना में एंट्री की 55 वर्ष से घटकर 50 वर्ष कर दी गई है, जो उम्रदराज लोगों के लिए काम नुकसानदार हो सकता है। इसके अलावा प्रीमियम में भी बढ़दी की गई है, जो कि 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। उद्घोग विशेषज्ञों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु की संभावना के कारण कंपनी अपने जीवित को कम करना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाइफ इंश्योरेस सेवाएँ नए एंडोरेंड नियम भी लागू किए हैं। एलआईसी का न्यू एंडोमेंट्स प्लान-914 न सिर्फ आपको सुखा करवा देता है बल्कि उपर्याप्त ज्ञान भी है। एंडोरेंड मृत्यु और परिवर्तन के लाभ एक साथ मिल जाते हैं। एंडोमेंट्स प्लान लाला इंश्योरेस पॉलिसी में आपको लाइफ करवा के साथ ही मैच्योरीटी बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके चलते पॉलिसी के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार को भुगतान किया जाता है। साथ ही मैच्योरीटी पर अलग लाभ मिलते हैं। हालांकि, लाला बदलावों के बारे में एलआईसी ने अब तक कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

6 जी की दौड़ में आगे बढ़ रहा भारत

नई दिली। भारत 6जी प्रैदेंगिकी के पेटेंट की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलावा-अलग अध्ययनों के आधार पर भारत इस मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। दिली एशिया में 15 अक्टूबर से पहली बार में विश्व टूरसंचार मानकीकरण असेंबली (डब्ल्यूपीएस) की मेंबरानी कर रहा है और यह 6जी के लिए मानक निर्धारण में इसके प्रभाव और भूमिका को निर्धारित कर सकती है। यह सम्प्रलग्न 190 देशों के प्रतिनिधियों को 6जी, आईपीएसल इंटर्लिंजेंस (एआई), बिग डेटा जैसे नुकसानदार सवालों की व्यापारिक समीक्षा के लिए भविष्य के मानक पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा। सम्प्रलग्न का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत का लक्ष्य आईपी का प्रमुख प्रदाता बनाना और किफायती 6जी समाधान उपलब्ध कराना है। वैश्विक आईपी प्रबंधन सेवाओं के लिए पेटेंट तथा ट्रेडमार्क लाइफ साइकल-मैसेसेल के आंकड़ों के अनुसार भारत 188 6जी पेटेंट के साथ दुनिया में छठे स्थान पर है। चीन 6,001 पेटेंट के साथ अमेरिका का कब्जा है। इसके बाद दिली कंपनिया (1,417), जापान (584) और यूरोपीय संघ (214) का स्थान आता है। ब्रिटेन (151), जर्मनी (84), स्वीडन (74) और फ्रांस (73) 6जी पेटेंट के मामले में भारत से पीछे हैं। ब्रिटेन के एक अध्ययन के अनुसार प्रथम स्थान लाइफ और प्रैदेंगिकी के लिए योग्य विद्युतीय बैंकों की ओर से ग्राहकों को आगे बढ़ावा दिलाया जाना चाहिए। इसके बाद दिली कंपनियों के लिए भविष्य के मानक पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा। सम्प्रलग्न का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

भारत का लक्ष्य आईपी का प्रमुख प्रदाता बनाना और किफायती 6जी समाधान उपलब्ध कराना है। वैश्विक आईपी प्रबंधन सेवाओं के लिए पेटेंट तथा ट्रेडमार्क-मैसेसेल के आंकड़ों के अनुसार भारत 188 6जी पेटेंट के साथ दुनिया में छठे स्थान पर है। चीन 6,001 पेटेंट के साथ अमेरिका का कब्जा है। इसके बाद दिली कंपनिया (1,417), जापान (584) और यूरोपीय संघ (214) का स्थान आता है। ब्रिटेन (151), जर्मनी (84), स्वीडन (74) और फ्रांस (73) 6जी पेटेंट के मामले में भारत से पीछे हैं। ब्रिटेन के एक अध्ययन के अनुसार प्रथम स्थान लाइफ और प्रैदेंगिकी के लिए योग्य विद्युतीय बैंकों की ओर से ग्राहकों को आगे बढ़ावा दिलाया जाना चाहिए। इसके बाद दिली कंपनियों के लिए भविष्य के मानक पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा। सम्प्रलग्न का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

नई दिली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली देश की विकासीली रिपोर्ट से धन भेजने में लागू वाले समय और लागत को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकासीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। आईपीआई गवर्नर ने इलेक्ट्रिक दोपहियों की ओलानक कार्रवाई हो रही है। इसके तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन और इंडिया (एआईएआई) ने एक अंतर्राष्ट्रीय मोटर घटाए जाने पर चिंता जारी है। एआईएआई ने कंपनी को 8 अक्टूबर को भेजे गए एक मेल में 'बॉस' सेल से पहले एस 1 एक्स 2 केडब्ल्यूएच (किलो वॉट आवर) मॉडल के दाम घटाए जाने के बारे में सुचित न किए जाने पर चिंता जारी है। इस प्रकार की चूक पीएम

की भारत सहित कई उभरती और विकासीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा पार यीर-टू-पीयर (पीएपी) भगतान की संभावनाओं को तलावाने के लिए धन प्रेषण पहला कदम है। हमारा मानना है कि इस तरह के धन प्रेषण की लागत और समय को काफी कम करने की ओर आपातकी कर रही है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय दोलर के आंकड़ों के अनुसार भगतान के लिए धन प्रेषण के संपर्क का विस्तार करने के प्रयास के पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। आगे आंकड़ों में इसकी जारीती दी गई है। आगे से धन के लिए धन प्रेषण के लिए धन अंतर्राष्ट्रीय दोलर के आंकड़ों में एंट्री की ओर से ग्राहकों को आगे बढ़ावा दिलाया जाना चाहिए। इसके बाद दिली कंपनीयों के लिए भविष्य के मानक पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा। सम्प्रलग्न का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ नई नियामकीय कार्टवाई

- कीमतों में अचानक कटौती पर स्पष्टीकरण मांगा

नई दिली।

इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ नई नियामकीय कार्रवाई हो रही है। इसके तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन और इंडिया (एआईएआई) ने कंपनी को 8 अक्टूबर को भेजे गए एक मेल में 'बॉस' सेल से पहले एस 1 एक्स 2 केडब्ल्यूएच (किलो वॉट आवर) मॉडल के दाम घटाए जाने के बारे में सुचित न किए जाने पर चिंता जारी है। इस प्रकार की चूक पीएम

की भारत सहित कई उभरती और विकासीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा पार यीर-टू-पीयर (पीएपी) भगतान की संभावनाओं को तलावाने के लिए धन प्रेषण पहला कदम है। इसनीं को मात्र 75,001 रुपये बताई है। इसनीं को मात्र 75,001 रुपये बताई है। एआईएआई भारी उद्योग मत्तालय के तहत एक वाहनों का परीक्षण करने पर चिंता जारी है। यह एजेंसी कंपनीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, विवर वर्ष 2024-25 में पंजाबहू इं-दोपहिया और इं-तिपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच और विवर वर्ष 2026 के लिए 2,500 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच के लिए कीमत 74,999 रुपये से घटकर 49,999 रुपये कर दी है।

रुपये से घटकर 49,999 रुपये कर दी है। मगर कंपनी ने एआईएआई को अपने इस मॉडल की एक्स-फैक्ट्री कीमत 75,001 रुपये बताई है। इसनीं को मात्र 75,001 रुपये बताई है। एआईएआई भारी उद्योग मत्तालय के तहत एक वाहनों का परीक्षण करने पर चिंता जारी है। यह एजेंसी कंपनीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, विवर वर्ष 2024-25 में पंजाबहू इं-दोपहिया और इं-तिपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच और विवर वर्ष 2026 के लिए 2,500 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच के लिए कीमत 74,999 रुपये से पहले का प्रस्ताव दिया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्स-फैक्ट्री कीमत 74,999 रुपये से घटकर 49,999 रुपये कर दी है।

मंगलवार 15 अक्टूबर 2024

भारत में चीन से घटिया स्टील हो रहा डंप.....मोदी सरकार सतर्क

नई दिली।

भारत सरकार चीन से आ रहे घटिया स्टील के आयात को अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में देश ने 3.45 मिलियन टन (एम्पी) स्टील का कठोर करने पर चाही रहा। यह बड़ी बात है। आयात में यह बढ़ती वैश्विक उत्पादकों की तरफ से किए गए एक विस्तृत विवरण के समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा में ग्लोबल लेवल पर ड्रेड डायवर्जन की वजह से इस आईपीओ के तहत कोई फेस शेयर जारी नहीं करेगा।

पहले पांच माह में, भारत स्टील का शुद्ध आयातक बन गया है। आधिकारिक अंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में देश ने 3.45 मिलियन टन (एम्पी) स्टील का कठोर करने पर चाही रहा। आयात में यह बढ़ती वैश्विक उत्पादकों की तरफ से किए गए एक विस्तृत विवरण के समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा में ग्लोबल लेवल पर ड्रेड डायवर्जन की वजह से इस आईपीओ के तहत कोई फेस शेयर जारी नहीं करेगा।

दौरान मांग भी कमजोर हुई है। इसके च

सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं कोर्ट ने माना

बेरेली कोर्ट ने रेप केस में युवक को बाइज्जत बरी किया

३ बच्चों की मां ने ३५ साल की उम्र में साल २०१९ में रेप का केस दर्ज कराया था.

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

उ.प. - बेरेली, झूठे मुकदमों में फंसे निर्दोष युवकों के लिए नजीर बन सकती है। अदालत ने दुष्कर्म मामले में बयान से मुकरने वाली युवती को उतने ही दिन जेल में रहने की सजा सुनाई है जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा। साथ ही उस पर पांच लाख ८८ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है जो निर्दोष को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की है।

बेरेली के कर्मचारी नगर की रहने वाली ३४ साल की महिला के तीन बच्चे हैं। आरोप है कि महिला के शिवम से संबंध थे और २०१६-२०१९ तक चले। इस पूरे मामले में महिला ने शिवम पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ ३ साल तक दुष्कर्म किया। २०१९ में महिला ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया।

अदालत ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए युवती ने सुरक्षा के



लिए बनाए गए कानून का दुस्योग किया। इस कानून के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती थी। झूठे मुकदमे की वजह से अरोप है कि महिला के शिवम से संबंध थे और २०१६-२०१९ तक चले। इस पूरे मामले में महिला ने शिवम पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ ३ साल तक दुष्कर्म किया। २०१९ में महिला ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया।

अदालत ने कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन बच्चों की मां शादी के झांसे में कैसे आ सकती है। महिला बालिग है। और हिंदू धर्म में महिला का तलाक नहीं हुआ है और वह शादीशुदा है। बेरेली, गाजियाबाद व मुरगाबाद के होटल में ले जाकर महिला को साथ रखा तो महिला पत्नी की तरह रही।

दो महीने बाद केस दर्ज कराने पर भी संदेह

घटना के एक साल दो माह बाद प्राथमिकी लिखाना भी संदेह कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज्यादा संदेह यह पैदा करता है कि घटना के एक साल दो माह बाद मामले में प्राथमिकी क्यों लिखाई गई जबकि, इस तरह की घटना में तत्काल प्राथमिकी लिखाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इतने समय में बह-चढ़कर तहरीर लिखने का समय मिल जाता है। संभवता इसीलिए लिखाई गई। इसी के साथ कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि कोई महिला घर से चार-पांच घंटे गायब रहती है तो परिवार वाले जरूर पूछते हैं कि इतनी देर कहां लगी? मगर इनके परिवार वालों ने नहीं पूछा? सबसे जरूरी कोर्ट में महिला यह भी नहीं बता पाई कि उसके साथ किन-किन नए लोगों ने दुष्कर्म किया। वीडियो की भी सत्यता नहीं मिली।

पुलिस की विवेचना पर उठे कई सवाल

बेरेली पुलिस की विवेचना पर जुलाई माह में भी सवाल उठे। जब फर्जी तरह से धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने रद्देगा, थाना प्रभारी और सर्किल के सीओ पर कार्रवाई के आदेश दिए। अब प्रेमनगर थाने की पुलिस की विवेचना पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बेरेली की अदालत में बेरेली पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी की विवेचना में पुलिस तथ्यात्मक

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने क्या कहा?

पूरे मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर का कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन न केवल वादी मुकदमा बल्कि अभियुक्त का भी मौलिक अधिकार है। न्यायालय पर वादी मुकदमा और अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि वादी मुकदमा या पुलिस की ओर से अधिकारों का दुस्योग किया जाता है और अभियुक्त को गलत केस में फंसाया जाता है तो वादी मुकदमा एवं पुलिस को निश्चित स्व से दंडित करना चाहिए। प्रश्नगत मामले में पुलिस की ओर से निश्चित स्व से सत्य और निराधार आरोप पल दाखिल कर अधिकारों का दुस्योग किया गया है।

झूठे मुकदमे की वजह से अजय को जेल में १६५३ दिन (चार साल छह महीने और आठ दिन) बिताने पड़े। वह २०१९ से आठ अप्रैल, २०२४ तक जेल में रहा। जज ने आरोपी युवती के झूठ की वाले सहयोगी की १५ साल की बहन का अपने साथ काम करने वाले दरोगा, प्रेमनगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर और सर्किल के सीओ पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है।

वजह से एक निर्दोष पर युवक को उप्रकैद व्यक्ति को जीवन के

की सजा हो सकती थी। बहुमूल्य साढ़े चार साल अरोपी को जेल में रहने जेल में बिताने पड़े। का कलंक झेलना पड़ा। इटी गवाही के आधार

फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने ३१ अगस्त को सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं।

साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन बच्चों की मां शादी के झांसे में कैसे आ सकती है। महिला बालिग है। और हिंदू धर्म में महिला का तलाक नहीं हुआ है और वह शादीशुदा है। बेरेली, गाजियाबाद व मुरगाबाद के होटल में ले जाकर महिला को साथ रखा तो महिला पत्नी की तरह रही।

दो महीने बाद केस दर्ज कराने पर भी संदेह

घटना के एक साल दो माह बाद प्राथमिकी लिखाना भी संदेह कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज्यादा संदेह यह पैदा करता है कि घटना के एक साल दो माह बाद मामले में प्राथमिकी क्यों लिखाई गई जबकि, इस तरह की घटना में तत्काल प्राथमिकी लिखाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इतने समय में बह-चढ़कर तहरीर लिखने का समय मिल जाता है। संभवता इसीलिए लिखाई गई। इसी के साथ कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि कोई महिला घर से चार-पांच घंटे गायब रहती है तो परिवार वाले जरूर पूछते हैं कि इतनी देर कहां लगी? मगर इनके परिवार वालों ने नहीं पूछा? सबसे जरूरी कोर्ट में महिला यह भी नहीं बता पाई कि उसके साथ किन-किन नए लोगों ने दुष्कर्म किया। वीडियो की भी सत्यता नहीं मिली।

पुलिस की विवेचना पर उठे कई सवाल

बेरेली पुलिस की विवेचना पर जुलाई माह में भी सवाल उठे। जब फर्जी तरह से धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने रद्देगा, थाना प्रभारी और सर्किल के सीओ पर कार्रवाई के आदेश दिए। अब प्रेमनगर थाने की पुलिस की विवेचना पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बेरेली की अदालत में बेरेली पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी की विवेचना में पुलिस तथ्यात्मक

साक्ष्य जुटाये बगैर चार्जशीट लगा देती है।

मेडिकल में शरीर में कहीं खरोंच के निशान नहीं थे, घटना के समय पहने कपड़ों को वह धो चुकी थी। साइबर सेल ने वीडियो की जांच की तब पता चला कि वह उसके पति के मोबाइल फोन से प्राप्त हुआ। इन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुकदमा कराया गया। जो वीडियो में महिला उन दोनों युवकों का विरोध

नहीं कर रही, बल्कि सहमति प्रतीत हो रही।

अश्लील वीडियो आरोपित युवकों से नहीं बल्कि महिला के पति के मोबाइल फोन से प्राप्त हुआ। इन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुकदमा कराया गया।

गया।

लखीमपुर विधायक को पीटने वाले ४ कार्यकर्ता भाजपा से बर्खास्त

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत चार भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

योगेश वर्मा ने सोमवार को

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ ३७ विधायक भी थे।

विधायक ने आरोपी

विधायक ने आरोपी के खिलाफ

कार्रवाई ना होने पर विधायक योगेश वर्मा ने नाराजगी जताई। बताया, 'मैंने मुख्यमंत्र